भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1382
28 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियां

1382. **डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कार्बन और प्रदूषक उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ उत्पादन बढ़ाने में इस्पात क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार इस्पात क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि रणनीति को किस प्रकार ऊर्जा दक्षता, हरित इस्पात, हाइड्रोजन-आधारित प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियाओं सहित डिकार्बनीकरण उपायों के साथ समन्वित कर रही है और इससे अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए घरेलू इस्पात उत्पादकों की तैयारी, रिपोर्टिंग तंत्र और विगत पांच वर्षों के दौरान प्रदान की गई सहायता सहित उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मंत्रालय कार्बन-संबंधित सीमा उपायों से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल व्यापार और प्रतिस्पर्धात्मक प्रभावों को कम करने के लिए अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ किस प्रकार समन्वय कर रहा है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) और (ख): इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्यबलों की सिफारिशों के आधार पर "ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रौडमैप और एक्शन प्लान" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस्पात क्षेत्र के समक्ष ग्रीन ट्रांजिशन में आने वाली चुनौतियों, ग्रीन स्टील और संधारणीयता के लिए रोडमैप, वर्ष 2070 तक निवल शून्य लक्ष्य की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का विवरण दिया गया है। यह रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): सरकार ने इस्पात क्षेत्र के ग्रीन ट्रांजिशन के लिए निम्नलिखित पहले शामिल की हैं:

(i) इस्पात मंत्रालय ने कम उत्सर्जन वाले इस्पात को परिभाषित और वर्गीकृत करने के लिए ग्रीन स्टील के लिए वर्गीकरण जारी किया है। ग्रीन स्टील वर्गीकरण ग्रीन स्टील के उत्पादन, बाजार निर्माण और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, अधिसूचित ग्रीन स्टील वर्गीकरण फ्रेमवर्क के तहत 90 इस्पात इकाइयों को ग्रीन स्टील प्रमाणन प्रदान किया गया है, जिसमें कुल 12.4 मिलियन टन ग्रीन स्टील का उत्पादन हुआ है।

(ii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चार पायलट परियोजनाएं प्रदान की गई हैं।

(iii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2010 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।

जारी...2/-

(iv) विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय कार्बन बाजार को विनियमित करने के लिए दिनांक 28.06.2023 को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) अधिसूचित की है, जो इस्पात संयंत्रों पर भी लागू होती है।

इस्पात मंत्रालय कार्बन से संबंधित सीमा उपायों से उत्पन्न होने वाले व्यापारिक प्रभावों को दूर करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ काम करता है।

*****